नई दिल्ली, 14 जून 2019 दैनिक जागरण

अधूरी परियोजनाओं को भी 'आदित्य' बनाएंगे योगी

धर्मेंद्र चंदेल • नोएडा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के इतिहास में पहली बार प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने शहर में आ रहे हैं। नोएडा की स्थापना 1976 व ग्रेटर नोएडा की स्थापना 1991 में हुई थी। दोनों शहरों में विकास के मामले में ऊंचाई हासिल की। राजस्व देने में भी यह जिला अव्वल है। दोनों की गिनती देश के आधुनिक शहरों में होती है।

उत्तर प्रदेश की सभी सरकारों ने राज्य में पूंजी निवेश के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा को शो विंडो के रूप में पेश कर सफलता प्राप्त की। हैरत की बात यह है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इन शहरों का हालचाल नहीं लिया। विकास की समीक्षा नहीं की। अधिकारियों ने जो फीड कर दिया, उसे मान लिया। यहीं कारण है कि प्रदेश के सबसे खूबसूरत कहे जाने वाले इन दोनों शहरों की गिनती आधुनिक नगर के बजाय घोटालों के गढ़ के रूप में की जाने लगी। यादव सिंह का नौ सौ करोड़ का टेंडर घोटाला, नीरा यादव का भूखंड आवंटन घोटाला व पीसी गुप्ता का जमीन खरीद घोटाला देश में चर्चा का विषय रहा। कारण प्रदेश के सीएम का इन शहरों से दूरी बनाना है।

दरअसल, प्राधिकरणों की स्थापना के बाद ही यहां अंधविश्वास हावी हो गया। जो भी मुख्यमंत्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा व दादरी आएगा, उसकी कुर्सी छह माह में चली जाएगी। हालांकि, इस अंधविश्वास को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने शासन काल में तोड़ा। वे अपने कार्यकाल में तीन बार नोएडा, ग्रेटर नोएडा आई, लेकिन कभी भी उन्होंने प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा नहीं की। सपा शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो पूरे पांच वर्ष नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दूरी बनाकर रखी। नतीजतन प्राधिकरणों में तैनात अधिकारी व स्थाई कर्मचारी बेलगाम हो गए।

मूल उद्देश्य से भटक गया प्राधिकरण: मुख्यमंत्री के नोएडा, ग्रेटर नोएडा न आने की वजह से दोनों प्राधिकरण अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। प्राधिकरणों की स्थापना औद्योगिक विकास के लिए हुई थी, ताकि राष्ट्रीय राजधानी के आसपास बड़ी संख्या में उद्योग लग सकें। यहां उद्योग की बजाय बिल्डर परियोजनाएं स्थापित कराने पर अधिक जोर हो गया। उद्योगों की जमीन बिल्डरों को दे दी गई। औद्योगिक विकास न लगने के कारण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों एवं किसानों के बच्चों को रोजगार नसीब नहीं हो सका।

नौवीं बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री ने कई बार अंधविश्वास को तोड़ा। वे 9 वीं बार जिले में आ रहे हैं। अब से वे युवा महोत्सव व नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो के उदघाटन के अलावा जनसभाओं को संबोधित करने आए थे। पहली बार वे प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

इन परियोजनाओं के लिए जगी उम्मीदछ: शहर में एक दर्जन परियोजनाएं ऐसी हैं, जो लंबे समय से अधर में पड़ी हैं। मुख्यमंत्री की नजर इन परियोजनाओं पर गई तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की विकास के मामले में तस्वीर बदल जाएगी।

कंवेंशन सेंटर: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 50 एकड़ जमीन कंवेंशन सेंटर का निर्माण होना था। इसकी डीपीआर भी बन चुकी है। यहां पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों के लिए बड़े-बड़े सभागार बनने हैं।

हेलीपोर्ट की ठंडे बस्ते में: ग्रेनो में 25 एकड़ जमीन पर हेलीपोर्ट बनना था। इसकी डीपीआर भी बन चुकी है। यहां से हेलीकाप्टर द्वारा चार धाम यात्रा शुरू करने की भी योजना थी।

बोड़ाकी रेलवे स्टेशन

स्टेशन के विस्तार की योजना भी 2003 में बनी थी। 250 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदी जा चुकी है। डीपीआर बन चुकी है। सिर्फ केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलनी बाकी है। स्टेशन बनने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों को पकड़ने के लिए दिल्ली व गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा। कई ट्रेन यहां से चलेंगी। इससे दिल्ली से भी बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। ट्रेनों की धुलाई व मरम्मत के लिए यहां सर्विस स्टेशन भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके बगल में लॉजिस्ट्रिक हब व ट्रांसपोर्ट हब का भी निर्माण होना है। बोड़ाकी तक मेट्रो ले जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड से पास हो चुका है।